इब्राहिम सुलेमान सेठ

बनाम

एम.सी. मुहम्मद और अन्य

7 नवंबर, 1979

[ए.सी. गुप्ता और पी.एस. कैलासम, जे.जे.]

भ्रष्ट व्यवहार - वापस लौटे उम्मीदवार के कथित भाषण का पूरा पाठ यह दिखाने के लिए कि उनका चुनावी भाषण धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देने का एक प्रयास था, जिसे प्रेस द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस बात के प्रमाण में स्वीकार किया गया था कि "भाषण का रिपोर्टर का संस्करण कमोबेश मेल खाता है" - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3ए) के अर्थ के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के संबंध में साक्ष्य में विश्वसनीयता।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 123 (3ए) दायरा और प्रयोज्यता - धारा 125 के प्रावधान अधिनियम की धारा 123 (3ए) के दायरे और अनुप्रयोग का पता लगाने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 123(3ए), क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघनकारी है।

केरल के मंजेरी संसदीय निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए अपीलार्थी के चुनाव को केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 मई, 1977 को प्रथम प्रतिवादी, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक था, द्वारा प्रस्तुत एक चुनाव याचिका पर इस आधार पर शुन्य घोषित कर दिया था कि लौटाया गया उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उप-धारा (3ए) में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण का दोषी था। आरोप यह

था कि चुनाव अभियान के दौरान अपीलार्थी ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पुलिकल नामक स्थान पर अंग्रेजी में भाषण दिया और मलयालम में अनुवादित इस भाषण की एक रिपोर्ट स्थानीय दैनिक चंद्रिका में 17 मार्च, 1977 के अंक में प्रकाशित हुई, जो अधिनियम की धारा 123 (3ए) की रिष्टि के दायरे में आती है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भले ही निर्वाचित उम्मीदवार के कथित भाषण का पूरा पाठ यह दिखाने के लिए कि उनका चुनावी भाषण धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देने का एक प्रयास था, प्रेस द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया था, प्रेस रिपोर्ट पर तब भरोसा किया जा सकता था जब कोई दूर का सुझाव भी नहीं था कि पूरे भाषण को प्रस्तुत करने के अभाव में ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और विशेष रूप से जब, तत्काल मामले में, अपीलार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि "इस समय की दूरी पर उसके लिए यह याद रखना संभव नहीं था कि उसने भाषण में वास्तव में क्या कहा था" और उस रिपोर्टर के भाषण का संस्करण "कमोबेश मेल खाता है"। [1151बी-सी]

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3ए) के दायरे और अनुप्रयोग का पता लगाने के लिए धारा 125 के प्रावधान प्रासंगिक नहीं हैं। यह सच है कि वह कार्य जिसे धारा 123 (3ए) में भ्रष्ट प्रथा कहा गया है, वह भी धारा 125 के तहत एक चुनावी अपराध है, लेकिन धारा 123 (3ए) को आकर्षित करने के लिए यह कार्य उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य द्वारा किया जाना चाहिए। उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से और उस उम्मीदवार के चुनाव को आगे बढ़ाने या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अन्य व्यक्ति, लेकिन धारा 125 के तहत कोई भी व्यक्ति दंडनीय है जो ऐसे कार्य का दोषी है और इसके पीछे का मकसद अधिनियम को अपराध का घटक नहीं बताया गया है। धारा 123(3ए) के दायरे

और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए धारा 123(3ए) और धारा 125 को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। [1152डी-एफ]

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, [1962] पूरक 2 एससीआर 769, विशिष्ट।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3ए) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन नहीं है। [1153ए]

जमुना प्रसाद मुखर्जी और अन्य बनाम लच्ची राम और अन्य [1955] 1 एससीआर 608; भरोसा किया।

4. एक भाषण, हालांकि इसका तत्काल लक्ष्य एक राजनीतिक दल है, फिर भी ऐसा हो सकता है जो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा दे। मतदाताओं पर भाषण के संभावित प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। [1153एच, 1154ए]

5. धारा 123 (3ए) के प्रावधानों के दायरे में आने के लिए, यह तथ्य महत्वहीन है कि चुनाव याचिकाकर्ता और निर्वाचित उम्मीदवार एक ही धर्म के थे। [1154ए-बी]

कुलतार सिंह बनाम मुख्तियार सिंह, [1964] 7 एस.सी.आर. 790 लागु किया।

6. सत्य धारा 123(3ए) के तहत भ्रष्ट आचरण के आरोप का जवाब नहीं है; जो प्रासंगिक है वह यह है कि क्या भाषण उस प्रावधान में उल्लिखित शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने की कोशिश करता है। यदि यह पाया जाता है कि ऐसा ही था, तो यह मायने नहीं रखता कि जो कहा गया वह तथ्यों पर आधारित था या नहीं। [1154एफ-जी]

वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि भाषण अधिनियम की धारा 123 (3ए) के तहत रिष्टि के दायरे में आता है। इसमें कोई शक नहीं कि भाषण का लहजा सांप्रदायिक था, लेकिन लेकिन इस देश में सांप्रदायिक दलों को राजनीति में काम

करने की अनुमति है। कानून किसी दल को अधार्मिक बताने पर भी कोई रोक नहीं लगाता है। भाषण में केवल मुस्लिम लीग (विपक्ष) की उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने की गलत नीति की आलोचना करने की कोशिश की गई जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के लिए जिम्मेदार थीं, न कि केवल अत्याचारों पर जोर देने की। [1155 बी, 1156 ए-बी]

कांति प्रसाद जयशंकर याग्निक बनाम पुरुषोत्तमदास रणछोड़दास पटेल और अन्य, [1969] 3 एस.सी.आर. 400; संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 11/1978

केरल उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका संख्या 18/77 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 6-12-77 से उत्पन्न।

एफ. एस. नरीमन, अनिल बी. दीवान, के. जे. जॉन, ए. एन. हक्सर, शकील अहमद और मंजिल कुमार, अपीलार्थी की ओर से।

पी. गोविंदन नायर और एन. सुधाकरन, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

गुप्ता, न्यायाधिपति.-

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत एक अपील है।

केरल के मंजेरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए अपीलार्थी के चुनाव को एर्नाकुलम में केरल के उच्च न्यायालय ने 3 मई, 1977 को पहले प्रतिवादी, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता था, द्वारा प्रस्तुत एक चुनाव याचिका पर इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया था कि निर्वाचित उम्मीदवार अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3 ए) में भ्रष्ट आचरण का दोषी था। अपीलार्थी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार था; हमारे सामने दूसरे प्रतिवादी ने मुस्लिम लीग के एक असंतुष्ट समूह के उम्मीदवार

के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसे "मुस्लिम लीग (विपक्ष)" के रूप में वर्णित किया गया था, जैसा कि चुनाव याचिका में कहा गया है, "जनता पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी"।

धारा 123 (3ए) में कहा गया हैः

> "123. भ्रष्ट आचरण- निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे -
>
> X X X
>
> (3ए) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निएवचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घ्रणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाती, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना ।

ऐसा कहा जाता है कि चुनाव अभियान के दौरान अपीलार्थी ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पुलिकल नामक स्थान पर अंग्रेजी में भाषण दिया था और इस भाषण की मलयालम में अनुवादित एक रिपोर्ट स्थानीय दैनिक चंद्रिका में 17 मार्च, 1977 के अंक में छपी थी, जो आरोपित है कि धारा 123(3ए) के तहत रिष्टि के अंतर्गत आता है। चुनाव याचिका में कई अन्य आरोप भी हैं लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में न्यायालय केवल इस आधार पर आधारित है, इसका उन्हें उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, भाषण की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) अंग्रेजी में दिए गए भाषण के सार का मलयालम में अनुवादित संस्करण है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री नरीमन ने तर्क दिया कि चूंकि भाषण का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं था, इसलिए रिपोर्ट के अनुसार भाषण से कोई निष्कर्ष निकालना असुरक्षित होगा। यह विवाद जो उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था, हमारी राय में, आक्षेपित निर्णय में पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया है। उच्च न्यायालय का कहना है:

> "यह सच है कि प्रदर्श पी-6 में पूरा भाषण शामिल नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लिखित बयान में इस आशय का कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि भाषण में अन्य अंश भी थे। पहले प्रतिवादी का जिसने प्रदर्श पी-6 में निहित बुराई को कम किया.... जब प्रथम प्रतिवादी ने आर.डब्ल्यू 1 के रूप में साक्ष्य दिया तो दूर-दूर तक संपूर्ण भाषण प्रदर्श पी-6 के उत्पादन के अभाव में कोई सुझाव नहीं था, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। पुनः, जब याचिकाकर्ता ने पी.डब्ल्यू 1 के रूप में साक्ष्य दिया तो उससे पहले प्रतिवादी द्वारा बोले गए अन्य मामलों, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था।"

उच्च न्यायालय में पहला प्रतिवादी हमारे समक्ष अपीलार्थी है। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए हलफनामा में, अपीलार्थी के स्वीकार किया कि हालांकि उनके लिए "इस समय यह याद रखना" संभव नहीं था कि उन्होंने भाषण में वास्तव में क्या कहा था, भाषण का रिपोर्टर का संस्करण बैठक में अपीलार्थी द्वारा दिए गए वीआई के साथ कमोबेश मेल खाता है। इसलिए हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि भाषण की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-6, पर भरोसा नहीं किया जा सकता है

चन्द्रिका में वर्णित भाषण इस प्रकार है:

"इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सुलेमान सैत ने आज पुलिकल में कहा कि समाज धर्म विरोधी लीग के लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जनसंघ की मदद की थी जिसने उत्तरी भारत और टेलिचेरी में कई मुसलमानों की हत्या कर दी थी और पवित्र मस्जिदों को जला दिया था। वहां के लोग गरीब मुसलमानों को साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादियों के खेमे की ओर भी ले जा रहे हैं इसलिए समाज उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि ये धर्म विरोधी लोग झूठ और झूठा प्रचार फैलाकर नेताओं के चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं और हमारे समाज के रहस्यों को मार्क्सवादियों और हिंदू नेताओं को दे रहे हैं। उन्होंने धर्म-विरोधी लीग को याद दिलाया कि ऐसा करके वे उस संस्था को नष्ट कर रहे हैं जिसे मरह्युम खाएदे मिल्लत इस्माइल साहब और बफ़ाकी थंगल ने पोषित और बड़ा किया था।

उन्होंने आगे कहा कि जनसंघ के मार्गदर्शन में बनी जनता पार्टी उन सभी राजनीतिक नेताओं का अनाथालय है, जिन्हें कोई सीट नहीं मिली या जो अपनी मूल पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा, इन दलों को विधानसभा या संसद देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म-विरोधी दलों को किसी भी मुस्लिम के वोट हासिल करने की मोटी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, जिनके सिर में इस्लाम का खून बह रहा है।

जनाब सैत साहब पुलिक्कल में आयोजित संयुक्त मोर्चा की सार्वजनिक बैठक में एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। बैठक की

अध्यक्षता चेरुकावु पंचायत अध्यक्ष पी.पी.अब्दुल गफूर मौलवी ने की।

बैठक का उद्घाटन पी.पी.उम्मारकोया ने किया।"

श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि यह विचार करने से पहले धारा 123 की उप-धारा (3ए) के वास्तविक दायरे और प्रभाव का पता लगाना आवश्यक है कि क्या भाषण उस उप-धारा की शरारत के अंतर्गत आता है और श्री नरीमन के अनुसार, उस उद्देश्य के लिए, धारा 123(3ए) को अधिनियम की धारा 125 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का भाग VII "भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध" से संबंधित है। धारा 123 भाग VII के अध्याय I में है जो भ्रष्ट आचरण को सूचीबद्ध करता है और धारा 125 उस भाग के अध्याय III में है जो चुनावी अपराधों को सूचीबद्ध करता है।

धारा 125 प्रदान करती है:

"125. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना- जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाती, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करेगा या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

यह सच है कि जिस कार्य को धारा 123(3ए) में भ्रष्ट आचरण कहा गया है, वही धारा 125 के तहत चुनावी अपराध भी है, लेकिन 123(3ए) को आकर्षित करने के लिए यह कार्य उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से और उस उम्मीदवार के चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, लेकिन

धारा 125 के तहत कोई भी व्यक्ति दंडनीय है जो ऐसे कृत्य का दोषी है और कृत्य के पीछे का मकसद अपराध का घटक नहीं बताया गया है। हमें कोई कारण नहीं मिला कि धारा 123(3ए) और धारा 125, दोनों प्रावधानों को धारा 123(3ए) के दायरे और प्रभाव का पता लगाने के लिए एक साथ क्यों पढ़ा जाना चाहिए। श्री नरीमन का तर्क यह है कि धारा 123(3ए) को धारा 125 के आलोक में पढ़ते हुए हमें यह मानना चाहिए कि हिंसा भड़काना या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना धारा 123(3ए) में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण की आवश्यकताओं में से एक है और इसमें इस मामले में उस पहलू पर किसी भी सबूत के अभाव में, अपीलार्थी के खिलाफ कथित भ्रष्ट आचरण को स्थापित नहीं किया जा सकता है। श्री नरीमन ने अपने तर्क के समर्थन में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का उल्लेख किया। केदार नाथ के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो राजद्रोह को अपराध बनाती है) को संविधान द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के रूप में सवाल उठाए जाने से बचाने के लिए, इस न्यायालय ने प्रावधान के आवेदन को कृत्यों तक सीमित कर दिया। जिसमें अव्यवस्था पैदा करने, या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, या हिंसा को उकसाने का इरादा या प्रवृत्ति शामिल हो। क्या अधिनियम की धारा 125 में उल्लिखित चुनावी अपराध को इस मामले में विचार के लिए समान घटक की आवश्यकता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; हमारी राय में धारा 125 के प्रावधान धारा 123 (3ए) के दायरे और अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। क्या धारा 123(3ए) को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करती है, इस प्रश्न का उत्तर जमुना प्रसाद मुखरिया और अन्य बनाम लच्छी राम और अन्य [(1)] में दिया गया है। उस मामले में इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(5) और 124(5), जैसा कि उस समय प्रावधान थे, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के

अधिकारातीत थे। धारा 124(5) जिसने "जाति, नस्ल, समुदाय या धर्म के आधार पर वोट देने या वोट देने से परहेज करने की व्यवस्थित अपील" को एक 'मामूली' भ्रष्ट आचरण बना दिया है, अधिनियम की धारा 123(3ए) के समान है जैसा कि यह अब मौजूद है। जमुना प्रसाद के मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए बोस, न्यायाधिपति ने कहा: "ये कानून किसी आदमी को बोलने से नहीं रोकते। वे केवल शर्तें निर्धारित करते हैं जिनका पालन करना होगा यदि वह संसद में प्रवेश करना चाहता है। उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और चुनाव लड़ने का अधिकार कोई सामान्य कानून अधिकार नहीं है। यह क़ानून द्वारा बनाया गया एक विशेष अधिकार है और इसका प्रयोग केवल क़ानून द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकार अध्याय का क़ानून द्वारा बनाए गए इस तरह के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं है। अपीलार्थी को संसद का निर्वाचित सदस्य बनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर वे चाहते हैं कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा. यदि वे इन नियमों के बाहर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करना पसंद करते हैं, तो विवादित धाराएं उन्हें नहीं रोकती हैं। हमारा मानना है कि ये धाराएं अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।" इसलिए हम श्री नरीमन द्वारा सुझाए गए धारा 123(3ए) के निर्माण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

श्री नरीमन का अगला तर्क यह था कि एक राजनीतिक दल को "वर्ग" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जिस अर्थ में "भारत के नागरिकों के वर्ग" की अभिव्यक्ति धारा 123(3ए) में उपयोग की गई है, अपीलार्थी ने जो कुछ भी कहा है भाषण एक राजनीतिक दल मुस्लिम लीग (विपक्ष) के खिलाफ था और इसलिए भाषण उस प्रावधान के दायरे में नहीं आया। हमें यह विचार करना आवश्यक नहीं लगता कि धारा 123(3ए) के अर्थ के अंतर्गत कोई राजनीतिक दल एक 'वर्ग' है या नहीं। निर्णय का प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दिया गया भाषण भारत के नागरिकों के

विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक भाषण, हालांकि इसका तात्कालिक लक्ष्य एक राजनीतिक दल है, फिर भी ऐसा हो सकता है जो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा दे। यह मतदाताओं के भाषण का संभावित प्रभाव है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमें श्री नरीमन द्वारा दिए गए एक अन्य तर्क में भी कोई तथ्य नहीं मिला कि धारा 123(3ए) इस मामले में लागू नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी और मुस्लिम लीग (विपक्ष) के उम्मीदवार दोनों मुस्लिम थे। कुलतार सिंह बनाम मुख्तियार सिंह [(1)] मामले में इस अदालत ने कहा कि धारा 123 के तहत एक उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण "मतदाताओं से उसके धर्म के आधार पर उसे वोट देने की अपील करके किया जा सकता है, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार उसी धर्म का हो" ।

ऊपर दिए गए भाषण के निम्नलिखित अंशों को आपत्तिजनक बताया गया है:

जैसा कि बताया गया है, भाषण के पहले पैराग्राफ में एक बयान है कि समाज धर्म-विरोधी लीग के लोगों, यानी मुस्लिम लीग (विपक्ष) को माफ नहीं करेगा, क्योंकि जनसंघ के साथ उनके गठबंधन ने उत्तरी भारत में और टेलिचेरी में भी कई मुसलमानों को मार डाला था। और मस्जिदों को जला दिया था और इससे भी आगे, ये लोग गरीब मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादियों के शिविर में ले जा रहे थे। रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है कि ये धर्म-विरोधी लोग "हमारे समाज" के रहस्य "मार्क्सवादियों और हिंदू नेताओं" को बता रहे थे। तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि स्पीकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन धर्म-विरोधी पार्टियों को मुसलमानों के वोट हासिल करने की आशा नहीं रखनी चाहिए "जिनके सिर में इस्लाम का खून बह रहा था"। श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि मुसलमानों की हत्या और मस्जिदों को जलाने के संबंध में आरोप तथ्यों पर आधारित थे और उन्होंने जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला

दिया जिसने 1971 में टेलिचेरी में हुई गड़बड़ी से संबंधित तथ्यों की जांच की थी। हमारी राय में सत्य धारा 123(3ए) के तहत भ्रष्ट आचरण के आरोप का उत्तर नहीं है; प्रासंगिक यह है कि क्या भाषण उस प्रावधान में उल्लिखित शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने की कोशिश करता है। यदि यह पाया जाता है कि ऐसा ही था, तो यह मायने नहीं रखता कि जो कहा गया था वह तथ्यों पर आधारित था या नहीं, खासकर तब जब इस मामले में उल्लिखित घटनाएँ वर्षों पहले घटी हों।

अब भाषण की ओर मुड़ते हैं तो मुसलमानों की हत्या और मस्जिदों को जलाने के आरोप जनसंघ जो कि एक राजनीतिक दल है, पर लगाए गए प्रतीत होते हैं। यह दावा नहीं किया गया है कि यह एक ऐसी पार्टी है जिसकी सदस्यता केवल हिंदुओं तक ही सीमित है। मुस्लिम लीग (विपक्ष) के सदस्यों को "धार्मिक विरोधी लोगों" के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने कांति प्रसाद जयशंकर याग्निक बनाम पुरूषोत्तमदास रणछोड़दास पटेल और अन्य [(2)] के मामले में कहा था, कानून किसी पार्टी को अधार्मिक बताने पर कोई रोक नहीं लगाता है। फिर कहा जाता है कि ये लोग मुस्लिम समाज के "रहस्यों" को "मार्क्सवादियों और हिंदू नेताओं" को "छोड़" रहे थे। यह स्पष्ट नहीं है कि उन "रहस्यों" की प्रकृति क्या थी जो हिंदू नेताओं और मार्क्सवादियों तक पहुंचाए जा रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूचना प्राप्त करने वालों में केवल हिंदू नेता ही नहीं बल्कि मार्क्सवादी भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषण उच्च प्रवाह भाषा में व्यक्त इस दावे के साथ समाप्त हुआ कि धर्म-विरोधी पार्टियों को "जिसके सिर में इस्लाम का खून बह रहा था" किसी भी मुस्लिम का वोट हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी।

भाषण को समग्र रूप से पढ़ने पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका स्वर सांप्रदायिक है, लेकिन इस देश में सांप्रदायिक पार्टियों को राजनीति में काम

करने की इजाजत है. ऐसा होने पर, मतदाताओं से अपील, जैसे कि प्रश्न में भाषण में की गई, को अधिनियम में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए, कुलतार सिंह बनाम मुख्तियार सिंह (सुप्रा) में न्यायालय की ओर से बोलते हुए गजेंद्रगडकर मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उल्लेखित किया गया है:

> "यह सर्वविदित है कि इस देश में कई दल हैं जो विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं की सदस्यता लेती हैं, लेकिन उनकी सदस्यता या तो विशेष समुदायों या धर्मों के सदस्यों तक ही सीमित है, या मुख्य रूप से उनके पास है। जब तक कानून ऐसी पार्टियों के गठन पर रोक नहीं लगाता है और वास्तव में उन्हें चुनाव और संसदीय जीवन के उद्देश्य के लिए मान्यता नहीं देता है, तब तक यह याद रखना आवश्यक होगा कि वोटों के लिए ऐसी पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा की गई अपील, सफल होने पर, नेतृत्व कर सकती है। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के विचार से प्रभावित हो सकता है। इस दुर्बलता को तब तक टाला नहीं जा सकता जब तक पार्टियों को कार्य करने की अनुमति दी जाती है और उन्हें मान्यता दी जाती है, हालांकि उनकी संरचना मुख्य रूप से विशेष समुदायों या धर्म की सदस्यता पर आधारित हो सकती है।"

आम मतदाताओं के मन पर भाषण के प्रभाव को इंगित करने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता ने दो गवाहों P.W.2 और P.W.4 से पूछताछ की। पी.डब्ल्यू.2 पी.सी.मोहम्मद ने कहा कि अपीलार्थी का भाषण सुनने के बाद, "मुस्लिम मतदाताओं ने उन लोगों को नफरत की नजर से देखा जो उनके खिलाफ खड़े थे", लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि भाषण में किस वाक्य से नफरत की भावना को बढ़ावा देने का

प्रयास किया गया, तो गवाह ने पहले वाक्य का हवाला दिया और उन्होंने खुद कहा कि "इस वाक्य का वास्तव में मतलब यह है कि जनसंघ के साथ एकजुट होना उचित नहीं है"। पी.डब्ल्यू.4 हिद्रे ने शुरुआत में यह भी कहा कि भाषण का उद्देश्य "सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना" था। लेकिन उन्होंने खुद बाद में अपनी गवाही में स्वीकार किया कि भाषण का एकमात्र प्रभाव यह था कि बैठक के बाद लोग ऐसा कह रहे थे "विपक्षी लीग के उम्मीदवार को हराना होगा"। हमें ऐसा लगता है कि भाषण में मुस्लिम लीग (विपक्ष) की उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने की गलत नीति की आलोचना करने की कोशिश की गई थी जो कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के लिए जिम्मेदार थीं, न कि केवल अत्याचारों पर जोर देने के लिए। हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता कि भाषण अधिनियम की धारा 123(3ए) की रिष्टि के अंतर्गत आता है; हम इस सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भ्रष्ट आचरण के आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।

अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है और चुनाव याचिका खारिज की जाती है।

वीडीके. अपील स्वीकार की गई।

(1) [1962] पूरक 2 एस.सी.आर 769

(1) [1955] 1 एस.सी.आर 608

19-743 एस.सी.आई./79

(1) [1964] 7 एस.सी.आर 790

(2) [1969] 3 एस.सी.आर 400

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****